12.29 hrs.

STATEMENTS OF PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

SHRI CHANDRAJIT YADAV: (Azamgarh): I lay on the Table English and Hindi versions of the following Statements:—

(1) Statement showing Action Taken by Government on the recommendations contained in Chapter I and final replies in respect of Chapter V of Ninety-eighth Report (Sixth Lok Sabha) on Dues and Equipment.

(2) Statement showing Action Taken by Government on the recommendations contained in Chapter I and final replies in respect of Chapter V of Hundred and eighteenth Report (Sixth Lok Sabha) on Ministry of Communications (P&T Board).

12.30 hrs.

MESSAGES FORM RAJYA SABHA

SECRETARY: Sir, I have to report the following messages received from the Secretary-General of Rajya Sabha:—

(i) "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha, at its sitting held on the 24th November, 1980, agreed without any amendment to the Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Trivandrum, Bill, 1980, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 17th November, 1980."

(ii) "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha, at its sitting held on the 24th November, 1980 agreed without any amendment to the Hindustan Tractors Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings) Amendment Bill, 1980, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 12th June, 1980."

12.31 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

REPORTED DELAY IN CONSTRUCTION OF GANGA BRIDGE AT PATNA

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर माननीय नौवहन और परिवहन मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और अनुरोध करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक बयान दें :

"पटना, बिहार में गंगा नदी पर पुल के निर्माण में कथित अनावश्यक विलम्ब, जिस के फलस्वरूप पुल के निर्माण की लागत में वृद्धि हो रही है ।"

THE MINISTER OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI VEERENDRA PATIL): Under the Constitution, Govt. of India are primarily responsible for roads declared as National Highways. All roads other than National Highways in a State, are essentially the responsibility of the State Government concerned.

The bridge under construction over the Ganga at Patna, when completed, would fall on a State road. It is, therefore, a State project and the Govt. of Bihar are primarily concerned. In order, however, to assist the State Government financially in

the construction of this bridge commenced in 1972, the Govt. of India agreed to provide in the 4th Plan a non-Plan loan not exceeding Rs. 4.5 crores towards 50 per cent of the expenditure on the bridge during that Plan, the entire balance being met by the State Govt. from their own resources. As there was no provision for such an assistance for this bridge under the subsequent Plans, the State Govt. have been financing this bridge since then entirely from their own resources. They are reported to have incurred a total expenditure of Rs. 41 crores so far including the non-Plan loan of Rs. 4.5 crores given to the State Govt. in the 4th Plan.

Being a State project, the State Govt. are dealing with all matters pertaining to this bridge covering planning, tendering, design and construction, supervision, etc. On the basis of a global tender, received by them, they awarded on 5-6-1972 the construction of this bridge to M/s. Gammon India Ltd. The State Govt. originally planned to complete this bridge by June, 1979 with 2-lane superstructure and 4-lane foundation. The State Government, however, could not adhere to this target date because of several reasons covering (1) shortage of materials, (2) shortage of power, (3) labour strike, (4) cyclone in April 1979 which led to the loss of three working gantries and damage to the casting bed on Patna side resulting in considerable delay, and (5) shortages of appropriate type/quality of cement since December, 1979.

As a result, the State Government's latest assessment is that hey would now be able to complete the bridge by December, 1981 with a 2-lane superstructure and 4-lane foundations. The bridge, when completed, is estimated by the State Govt. to cost Rs. 46 crores.

According to the information available from the State Govt. this escalation in the cost is attributable to (i) increase in scope of work of the foundation and substructure from 2-lane bridge to 4-lane based on the accepted tender and (ii) further escalation in the prices of materials, labour wages, increase in land acquisition cost, etc.

Since it is a State project, it is now essentially for the State Govt. to take appropriate action to complete the balance of the work as early as possible.

श्री रामविलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, मुझे भी यही उम्मीद थी कि उन की तरफ से इसी तरह का जवाब आयेगा। एक तरफ सरकार राष्ट्रीय महत्व के विषय की चर्चा करती है लेकिन सरकार ने जो जवाब दिया है उस से ऐसा लगता है कि इस पुल का कोई राष्ट्रीय महत्व ही नहीं है। पिछले दिनों स्पीकर साहब पटना गये जो पहले मंत्री श्री ए० पी० शर्मा थे या जो भी मंत्री वहां जाते हैं यही भाषण दे कर आ जाते हैं कि पुल बन जायगा। चानना साहब भी यहां बैठे हुए हैं, इन से भी हम ने बातचीत की। इन्होंने भी कहा, रामविलास जी, पुल का काम 15 दिनों में शुरू हो जायेगा और आप ने कहा कि सीमेंट की कमी नहीं रहेगी और अब आप ने कहा है कि देरी के कारण निर्माण सामग्री का अभाव है। पहले तो सीमेंट में देरी हुई और फिर आप ने सीमेंट कैसा भेजा ? आप ने सीमेंट उड़ीसा से ऐसा भेजा जिस को चीफ इंजीनियर ने रिजेक्ट कर दिया। अब पैसे न मिलने के अभाव में रिजेक्ट किया, आप का सीमेंट बहुत अच्छा था लेकिन चीफ इंजीनियर को पैसा नहीं मिला, इसलिए रिजेक्ट कर दिया या सचमुच में आप के सीमेंट की खराबी थी ? अगर ऐसी बात है तो फिर आप का जो क्वालिटी कन्ट्रोल विभाग है, वह क्या करता है। जब सीमेंट उठाया जा रहा था, उस समय क्यों नहीं इस बात को देखा गया। हजारों टन सीमेंट जब गंगा ब्रिज पर

[श्री रामविलास पासवान]

चला गया, तब कह दिया कि सीमेंट खराब है । तो में यह कह रहा हूं कि सरकार ने जो जवाब दिया है क्या इस ढंग का जवाब सरकार को देना चाहिए उस ने ऐसा जवाब दिया है जैसे यह राष्ट्रीय महत्व की चीज नहीं है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप से आग्रह करता हूं कि यह 5,572 मीटर लम्बा पुल है और यह पुल न सिर्फ उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार को जोड़ता है बल्कि यह नेपाल जाने का मार्ग भी सुलभ करता है और यदि यह पुल बन जाता है तो पटना से नेपाल की दूरी 120 मील कम हो जाती है । मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उस में कोई दम नहीं है और मैं तो यह आशा करता था कि पाटिल साहब जवाब देंगें, तो उन का जो स्वविवेक है, उस स्वविवेक को भी वे इस्तेमाल करेंगे । आप ने कारण दिया कि सीमेंट का संकट है । पहले तो आप ने सीमेंट का बहाना बनाया और जब सीमेंट आया, तो उसे बेकार साबित कर दिया गया । जब दोबारा सीमेंट आने का सवाल आया, तो कह दिया गया कि क्रेन काम नहीं कर रहा है और क्रेन की मरम्मत हो रही है । मैं तो यह कहूंगा कि यह सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है । यह पुल वह मुर्गी है जो सोने का अंडा देती है । उस पुल की क्या लागत आएगी, पता नहीं इस का जवाब आप ने दिया है या नहीं लेकिन शुरू में 20 करोड़ रुपये इस की लागत का अनुमान था, 20 करोड़ रुपये एस्टीमेटेड कास्ट थी और आज 46 करोड रूपये उस पर खर्च हो चुके हैं और 46 करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद भी अभी तक यह पता नहीं कि वह कब तक पूरा होगा । रोज अखबारों में इस के बारे में खबरें आ रही है और मैं बहुत सारी प्रेस केटिंग्स रखे हुए हूं । मंत्री महोदय ने वे पढ़ ली होतीं, स्टेट गवर्नमेंट से जवाब तलब करने के बजाय अगर उन को पढ़ लिया होता, तो पता चल जाता कि इस में कितनी बड़ी बंगलिंग और कितना कुछ हुआ है । 20 करोड़ रुपये की लागत के पुल पर 46 करोड़ रुपये खर्च हो जायें और तब भी अभी जो पुल की स्थिति है, वह अगर आप 'दूडे' को देखें तो पता चलेगा कि वह पुल ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है । मैंने पहले कहा था कि जिस तरीके से यह पुल बन रहा है, वह शीघ्र नहीं बन पाएगा और मंत्री महोदय का जवाब है कि 1981 तक पूरा हो जाएगा । अगर इसी तरह से काम चला तो मैं कह सकता हूं कि 2,000 ई० तक भी वह नहीं बनेगा , 2,000 ई० तक भी वह नहीं बनने वाला है । इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप से आग्रह करता हूं कि जब कोई मंत्री जवाब दे, तो पूरी जिम्मेदारी से जवाब दें । यह नहीं होना चाहिए कि एक मंत्री जब आ गये, तो कुछ जवाब और उस के बाद जब दूसरा मंत्री आए, तो कुछ और जवाब, एक ही सरकार के विभिन्न मंत्री जवाब देते हैं । यह नहीं होना चाहिए ।

हमारे पास यह एक बहुत लम्बा खत है, जो कि मेरे नियम 377 के जवाब में श्री ए० पी० शर्मा जी ने लिखा था । उन्होंने इस बात को कबूल किया था कि जब वे वहां गये थे, तो वहां की सरकार, वहां के राज्यपाल ने यह कहा था कि यह पुल बनाना हमारे बलबूते के बाहर है, बिहार सरकार के बस के बाहर की बात और वहां के राज्यपाल ने उस पुल को बनाने के लिए लिखा था और मंत्री जी ने अपने पत्र में यह लिखा था कि वे इस से सहमत हैं और लिखा था कि "वित्तीय सहायता देने के प्रश्न पर बराबर बातचीत कर रहां हूं ताकि विचाराधीन पुल का निर्माण शीघ्र से शीघ्र हो जाये" । यह आप के मंत्री जी का जवाब है श्री ए० पी० शर्मा जो उस समय शिपिग एण्ड ट्रांसपोर्ट मंत्री थे उस समय उन का यह जवाब आया था और

अब भी जो आप ने जवाब दिया है उस से ऐसा मालूम पड़ता है कि सारा का सारा स्टेट गवर्नमेंट को करना होगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, तो वह पुल जहन्नुम में जाए, केन्द्र सरकार का इस से कोई मतलब नहीं रह गया है। इसलिए मैं आप से आग्रह करता हूं कि ये जो सारी चीजें है, इन को मंत्री जी देखें। मंत्री जी को इन की जानकारी होगी। अगर वे प्रेस कटिंग्स को पढ़े होंगे तो उन को पता चला होगा कि इस पुल के लिए जो सीमेंट आया, पुल के निर्माण के लिए जो लोहा आया या दूसरी चीजें आईं, वे सारी की सारी नेपाल में चली गईं। अधिकांश माल वहां चला गया। जब देश के विभिन्न राज्यों में इतनी सारी बिल्डिगें बन गई हैं, तो यह पुल क्यों नहीं बना ?

हम को एक शंका और भी है और कई पेपर्स में भी यह चीज निकली है। इस देश में जो बड़े लोग हैं, उन की मोनोपली सब चीजों पर है, चाहे वह रेलवे की मोनोपली हो, चाहे ब्रिजों की मोनोपली हो और चाहें किसी और चीज की मोनोपली हो। मंत्री जी को इस की जानकारी होनी चाहिए। उसी पटना से उसी पुल की दूरी तक वहां के एक बहुत बड़े आदमी का स्टीमर चल रहा है और वह बराबर चल रहा है। आपका जहाज खराब हो जाएगा लेकिन उस बड़े आदमी का जहाज कभी खराब नहीं होगा। रेलवे का जहाज खराब होगा, तो सब उसके जहाज से जायेंगे, सभी चीजें उस तीन किलोमीटर रास्ते पर उसी के जहाज से जायेंगी। वह आदमी बराबर काम कर रहा है।

सुना है कि इस पुल के निर्माण में भी जो देरी की जा रही है वह भी उसी आदमी की वहज से की जा रही है। वह आदमी करोड़ों रुपये खर्च कर सकता है। अगर इस पुल का निर्माण हो जाता है, तो उस पर से मोटर गाड़ी जाएगी, आदमी जाएंगे। फिर उसके जहाज से कौन जाएगा ? मैंने पंडित कमलापति त्रिपाठी जी से भी बात की थी, एक समस्या के संबंध में बात की थी लेकिन वह हो नहीं सकी।

इस तरह से ये बड़े बड़े लोग अपनी मोनोपली कायम किये हुए हैं। अभी गेमन्स कम्पनी का नाम लिया गया। मैं जानना चाहता हूं कि इस गेमन्स कम्पनी के साथ क्या शर्तें तय हुई हैं, क्या उसकी कार्य क्षमता है। इसके बारे में सरकार ने नहीं बताया है। पता नहीं सरकार उस कम्पनी से क्यों डरती है ? क्या इस कम्पनी के साथ यह शर्त भी तय है कि यदि सरकार की लापरवाही के कारण कार्य में कोई विलम्ब होता है तो सरकार को 25 हजार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से इस कम्पनी को हर्जाना देना होगा। मैं जानना चाहता हूं कि इस हर्जाने के तौर पर अब सरकार द्वारा इस कम्पनी को कितनी राशि दी गयी और काम में लापरवाही के लिए कौन पदाधिकारी जिम्मेदार थे ? यह सारी बातें आपको जवाब में बतानी चाहिए थीं जिनको कि आपने नहीं बताया है।

मैं पूछना चाहता हूं कि जो ब्रिज बनाया गया है उसके बारे में जो गेमन्स कम्पनी के साथ कांट्रेक्ट हुआ, उसको अब तक कितना रुपया हर्जाना के तौर पर सरकार ने दिया है और हर्जाने के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं ? गेमन्स की कितनी जगहों पर सरकारी एजेंसियां हैं और उसकी कार्यक्षमता क्या है ?

मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या बिहार सरकार ने या वहां के राज्यपाल ने केन्द्रीय सरकार को लिखा है या नहीं कि केन्द्रीय सरकार इस पुल को अपने हाथ में ले ले। यह देश का एक बहुत महत्वपूर्ण पुल है। ऐसे राष्ट्रीय महत्व के

[श्री रामविलास पासवान]

पुल चाहे कहीं पर भी हों केन्द्रीय सरकार को अपने हाथ में ले कर उन्हें बनाना चाहिए। क्या केन्द्रीय सरकार इस महत्व-पूर्ण पुल को अपने हाथ में ले लेगी या ऐसे ही खर्च करती जाएगी। क्या केन्द्रीय सरकार यह भी देखेगी कि इस पर खर्च होने वाली राशि सही ढंग से खर्च हो रही है, उसका उपयोग सही ढंग से हो रहा है या नहीं ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो अभी कुछ प्रश्न पूछे उनसे ऐसा लगता है कि जो कालिंग अटेंशन नोटिस उन्होंने पूछा है और उसका जो मैंने जवाब दिया है उसको उन्होंने समझा ही नहीं।

मैंने अपने जवाब में साफ तौर पर कह दिया था कि यह प्रोजेक्ट गवर्नमेंट आफ इंडिया का नहीं है। यह जो गंगा पर पुल बन रहा है, यह स्टेट का है और स्टेट रोड पर बन रहा है। स्टेट रोड पर पुल बनाने की सारी जिम्मेदारी स्टेट मगर्नमेंट की होती है न कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट की। अगर नेशनल हाईवेज पर कोई रोड अगर है तो उस पर ब्रिज बनाने की जिम्मेदारी सेन्ट्रल गवर्नमेंट की है। लेकिन जब स्टेट के अन्दर बहुत सी सड़कें बनती हैं, उन पर ब्रिज बनते हैं, तो उनके बारे में सारी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की होती है। वही उनके बारे में प्लान बनाती है, वही टेंडर मांगती है, वही उनको बनाने के लिए एजेंसी मुकर्रर करती है। इसमें उन्होंने ओपन टेंडर मांगे जब कांट्रेक्ट दिया, या बुला कर वैसे ही फिक्स किया, क्या किया, क्या हर्जाना दिया, उसके बारे में हम को कुछ नहीं मालूम है क्योंकि हम उनके बीच में नहीं आते हैं। लेकिन चूंकि यह बहुत बड़ा ब्रिज है, इसकी 5.7 किलोमीटर लेंथ है।

मैं मानता हूं कि यह बहुत बड़ा ब्रिज है और पहले इसका एस्टीमेट 23 करोड़ 50 लाख का हुआ था। उस वक्त टू लेन केरिज का ही बनाने का विचार किया गया था, लेकिन जब टेंडर हुआ उस समय सोचा गया कि यह बहुत बड़ा ब्रिज है और इसे हम कोई 5—10 या 15 साल के लिए तो बना नहीं रहे हैं यह तो सदियों के लिए बन रहा है इसलिए फोर लेन केरिज पर होना चाहिए। तब इसका डिजाइन बदला गया और जिसकी वजह से 23 करोड़ 50 लाख के बजाय 46 करोड़ एस्टीमेट हो गया।

श्री रामविलास पासवान : अभी खर्चा 46 करोड़ हो चुका है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : अभी 41 करोड़ रुपए खर्चा हुआ है। बिहार सरकार कह रही है कि यह ब्रिज पूरा करने के लिए और 5 करोड़ रुपए लगेंगे। उनके हिसाब से रिवाइज एस्टी-मेट के लिहाज से 46 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अब सवाल यह है कि जब वे यह काम लेना चाहते थे उस वक्त भारत सरकार से उन्होंने कहा कि यह बहुत बड़ा काम है और हमारे पास इतने रिसोर्सेस नहीं है, हम इतना खर्च नहीं कर सकते आप कुछ इमदाद कीजिए। क्योंकि प्रोजेक्ट हमारा नहीं था, ब्रिज हमारा नहीं था, रोड भी हमारा नहीं था, नेनशल हाईवे का प्रोजेक्ट भी नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का ब्रिज है, फिर भी यह सोच कर कि बहुत बड़ा काम है इसलिए कहा कि हम फोर्थ प्लान में साढ़े चार करोड़ रुपया आपको देंगे।

श्री रामविलास पासवान : 50 प्रतिशत देने की बात थी ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं उस बात का एक पोर्शन पढ़कर सुनाऊंगा—

"It has to be clearly understood that no additional assistance would be available for the completion of

the project after the 4th Plan period and the State Government will have to find the necessary funds within the State Plan."

साढ़े चार करोड़ रुपया मंजूर करते वक्त हमने साफ तौर पर स्टेट गवर्नमेंट को कह दिया था कि साढ़े चार करोड़ रुपये से ज्यादा हम देने वाले नहीं हैं। इसके ऊपर जितना भी खर्च होगा वह आपको अपने रिसोर्सेस से करना पड़ेगा। हम इससे ज्यादा देने वाले नहीं हैं। लेकिन अब खर्चा बहुत बढ़ गया है। वे लोग 41 करोड़ रुपया खर्च कर चुके हैं। अब बिहार सरकार, मुख्य मंत्री, गवर्नर, सब हमको लिख रहे हैं कि हमको और इमदाद दीजिए, क्योंकि हमने इतना खर्च किया है, करीबन 35-36 करोड़ खर्च कर लिया है। हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है इसलिए आप कुछ और नान प्लान या आउटसाइड प्लान लोन दीजिए। वे कह रहे हैं, लेकिन हमने अभी इसके बारे में कोई तसफिया नहीं किया है।

श्री राम विलास पासवान : वही तो पूछ रहें हैं कि क्या करने जा रहे हैं ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मुख्य मंत्री के लैटर्स मेरे पास आए हैं, गवर्नर लैटर्स आए हैं, बिहार सरकार के लैटर्स आए हैं ; वे कहते हैं कि अब तक हमने जो खर्च कर लिया है, लेकिन अब हमारे से नहीं होगा और कुछ हमको मदद दीजिए। उसके बारे में सोच रहे हैं, अभी तक कोई तसफिया नहीं हो पाया है क्योंकि यह नान प्लान एक्सीपेंडीचर है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: In view of this calling attention by Shri Paswan, you may consider it favourably.

SHRI VEERENDRA PATIL: They have asked for additional assistance outside the plan. There is a procedure for that. I have to go to the Planning Commission and the Finance Ministry. Unless the Planning Commission clears and the Finance Ministry concurs, I cannot give any assurance to the hon. Member here.

SHRI CHANDRAJIT YADAV (Azamgarh): Will you take initiative?

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, आज से 3 महीने पहले आपके मंत्री श्री ए० पी० शर्मा ने लिखा है कि वे बात कर रहे हैं और आप कहते हैं कि विचार कर रहे हैं, ये दोनों मंत्रियों का कैसा जवाब है ?

श्री चन्द्रजीत यादव : पढ़कर सुना दीजिए जो इस में लिखा है।

श्री राम विलास पासवान : इस में यह लिखा हुआ है :

> तभी से मैं सभी संबंधित पक्षों से बिहार सरकार को वित्तीय सहायता देने के प्रश्न पर बराबर बातचीत कर रहा हूं ताकि विचाराधीन पुल का निर्माण कार्य शीघ्र से शीघ्र पूरा हो जाए।

आप कहते है कि अभी कुछ हुआ ही नहीं है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैंने साफ कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट हमें लिख रही है, चीफ मिनिस्टर हम को परसनल लैटर लिख रहे हैं और यही नहीं परसनल लैटर फाइनेंस मिनिस्टर को, प्लानिंग कमिशन को भी उन्होंने लिखें हैं। इसीलिए मैंने कहा कि अगर एडीशनल कुछ लोन हम को देना है तो उसके लिए प्रोसीजर है और उसी के बारे में शर्मा जी ने जिक्र किया है अपने पत्र में कि मैं पत्र व्यवहार कर रहा हूं या संबंधित लोगों से बातचीत कर रहा हूं। यह नान प्लान एक्सपेंडीचर है। यह हमारा प्रोजेक्ट नहीं है। जितनी भी हम सहायता दे सकते हैं वह प्लानिंग कमिशन और फाइनेंस मिनिस्टरी से कंसलटेशन के बाद उनके कनकरेंस के बाद ही दे सकते

[श्री वीरेन्द्र पाटिल]

हैं । उसके पहले देने का सवाल पैदा नहीं होता है । मैं दोनों से बातचीत करूंगा और उनकी कनकरेंस अगर मिली तो मैं असिस्टेंस देने की स्थिति में होऊंगा ।

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : गंगा नदी पर जो पुल का निर्माण हो रहा है यह सिर्फ प्रान्त से कंसर्ड नहीं है । यह राष्ट्रीय महत्व की चीज है । जितना विलम्ब हो रहा है उतनी राष्ट्र की आर्थिक क्षति हो रही है । दस वर्ष पूर्व इस पुल का शिलान्यास प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था । यह भी सही है कि इस बीच सभी वस्तुओं के दाम बहुत बढ़ गए हैं । सीमेंट का दाम बढ़ गया है, लेबर चेंजिज में संशोधन हो गया है । उसके कारए भी इस पर आने वाले खर्च में बढ़ोतरी होती चली गई है । रिवाज्ड कास्ट जो है वह अब 46 करोड़ हो गई है । जैसा अभी मंत्री जी ने कहा बिहार सरकार की पी डब्ल्यू डी के जितने भी अनुबंध थे वे सारे इसी पर खर्च हो गए हैं और सारा धन इस पुल के निर्माण में खर्च हो गया है । इस कारण से बिहार में दस वर्ष से कोई भी सड़क निर्माण का काम नहीं हुआ है । इससे बिहार की प्रगति अवरुद्ध हो गई है । मंत्री महोदय ने कहा है कि यह बिहार सरकार की योजना है और उनका इससे कोई सरोकार नहीं है । मैं इसको नहीं मान सकती हूं । जब यह राष्ट्र से संबधित है और राष्ट्रीय क्षति हो रही है तो जरूर उनका इससे संबंध जुड़ता है । इन दस वर्षों में पैट्रोल, डीजल के दाम बहुत अधिक बढ़ गए हैं और इनकी कमी भी हो गई है । सीमेंट की कीमत भी बढ़ती जा रही है और उसकी कमी महसूस की जा रही है । इन कारणों से दस करोड़ इस पर अतिरिक्त खर्च आने का अनुमान है । इस बीच अगर पुल का निर्माण हो गया होता तो आज पैट्रोल और डीजल में जो खर्च हो रहा है, टी ए डी ए में सरकार का जो खर्च हो रहा है वह सब बच जाता और इस तरह से दस पंद्रह करोड़ की बचत हो सकती थी ।

विलम्ब के कारण यहां बताए गए हैं । मैं जानना चाहती हूं कि क्या यह सही नहीं है कि बिहार सरकार ने पंद्रह हजार मैट्रिक टन सीमेंट की मांग की थी जब कि उसको केवल छः हजार मैट्रिक टन ही दिया गया ? जो दिया भी गया वह ऐसा सीमेंट था जिससे पुल का निर्माण नहीं हो सकता था और वह घर बार वगैरह बनाने में इस्तेमाल हो गया । क्या यह सब सहीं नहीं है ?

माननीय सदस्य ने अभी शर्मा जी का, चानना जी का नाम दिया । ये भी तीन साल तक शासन की बागडोर सम्भाले रहे । तब इन्होंने इस परियोजना की वकालत ठीक से नहीं की । जनता पार्टी सरकार से पर्याप्त राशि का प्रावधान करने के लिये उस पर जोर नहीं डाला जिसके कारण काफी विलम्ब हुआ है । यह आज का ही विलम्ब नहीं है, यह पहले से ही चला आ रहा है । इस पर भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए, यह आवश्यक है । लेकिन पिछले तीन वर्षों से राशि का प्रावधान नहीं हो सका और इस पर इस समय इतना ध्यान नहीं दिया गया । मैं मंत्री महोदय से कहना चाहती हूं और जानना चाहती हूं कि वहां जो सीमेंट का अभाव है क्या वह उसकी आपूर्ति जल्दी से जल्दी करेंगे ताकि अगर 1981 में नहीं हो सके तो कम-से-कम 1982 में तो यह पुल बनकर तैयार हो जाये ।

इसके अलावा जो भी सरकार बनी है, चाहे जनता पार्टी की हो या हमारी पार्टी की हो, सब ने यह आश्वासन दिया है कि यह बहुत बड़ी राशि है और इसे बिहार सरकार खर्च नहीं कर सकती है, इसलिये भारत सरकार आधी राशि देगी और हमेशा इसमें सिम्पैथैटिक कंसीडरेशन

की बात है । मैं जानना चाहती हूं कि 5 करोड़ की जो राशि इसमें लगेगी क्या वह भारत सरकार देगी और क्या सीमेंट की आपूर्ति करेगी जिससे 1981 या 1982 तक यह पुल बनकर तैयार हो जाये ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : सवाल यह पूछा गया है कि जो 5 करोड़ रुपये और लगेंगे क्या वह गवर्नमेंट आफ इंडिया देगी ? अब हुआ यह है कि बिहार गवर्नमेंट 23 करोड़ रुपये के बारे में हमसे पूछ रही है, एडीशनल लोन देने के लिए मांग कर रही है । 5 करोड़ तो टू-लेन कैरिज-वे के लिये लग जायेगा और उनका प्रपोजल यह है कि फोर-लेन कैरिज-वे होना चाहिये इसलिये फोर-लेन कैरिज-वे का सुपर स्ट्रक्चर होना है तो उसके लिये एडीशनल 18 करोड़ रुपया चाहिये । इस तरह से 18 करोड़ यह और 5 करोड़ रुपया पहले के एस्टीमेट का है, इस तरह से 23 करोड़ रुपया वह पूछ रहे हैं ।

23 करोड़ रुपये मैं आज ही दे दूंगा, यह कहने की हालत में नहीं हूं । यह 23 करोड़ रुपये का आउट साइड दी प्लान लोन देने का सवाल है । इसलिये मैंने कहा है कि प्लानिंग कमीशन और फाइनेन्स मिनिस्टर से डिसकस करूंगा और जितना मेरे से हो सकता है, मैं पूरा प्रयत्न करूंगा लेकिन आज कोई भी आश्वासन देने की हालत में मैं नहीं हूं । इसलिये मैं कोई आश्वासन नहीं दे सकता, लेकिन मैं प्रयत्न करूंगा, इतना कह सकता हूं ।

माननीया सदस्या ने यह सवाल पूछा कि सीमेंट सप्लाई न होने की वजह से यह काम धीमा हो रहा है, ठीक तरह से नहीं चल रहा है । मैं अभी चानना साहब से रिक्वैस्ट करूंगा कि इसके लिये स्पेशल सीमेंट की जरूरत है, पोर्टलैंड सीमेंट की जरूरत है, बिहार में जो सीमेंट मिलता है वह इस काम के लिये ठीक नहीं है, यह सीमेंट तमिलनाडु से लाना पड़ेगा, अब चाहे तमिलनाडु से लाना पड़े या कहीं से भी लाना हो इस ब्रिज के लिये जो भी सीमेंट लगना है वह मैं अपने मित्र चानना साहब से रिक्वैस्ट करूंगा कि टाप-प्रायर्टी पर इस सीमेंट की सप्लाई करवाने की व्यवस्था करें । हम लोग भी पूरी तरह से प्रयत्न करेंगे कि जहां तक हो सके उनका जो टारगैट डेट है दिसम्बर, 1981 तक खत्म होने का उसके अन्दर ही यह ब्रिज पूरा करने के प्रयत्न हम करेंगे ।

12.58 hrs.

PETITION *RE*: DELHI MUNICIPAL LAWS (AMENDMENT AND VALIDATION) BILL, 1980

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : श्रीमन्, मैं दिल्ली नगर पालिका विधि (संशोधन और वैधीकरण), विधेयक, 1980 के संबंध में श्री पी० एन० नारंग द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूं ।

12.59 hrs.

MOTION *RE*: JOINT COMMITTEE ON OFFICES OF PROFIT

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI P. SHIV SHANKAR): I beg to move:

"That a Joint Committee of the Houses to be called the Joint Committee on Offices of Profit be constituted consisting of fifteen members, ten from this House and five from the Rajya Sabha who shall be elected from amongst the members of each House in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote: